पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मई, 2022 ई0 (बैशाख 17, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–19

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	513–537	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	533–540	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

13 अप्रैल, 2022 ई0

संख्या–146 / VII-A-2/2022/11(सिडकुल)/2021–राज्यपाल, कार्यालय ज्ञाप सं0–1269 / VII–A–2 / 2021 / 11–सिड़कुल / 2021 दिनांक 25.10.2021 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) प्रस्तर–1 में:–

(i)स्तम्भ (1) में दिये गये खण्ड (छ) के विद्यमान प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्रावधान रख दिये जाऐंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान प्रावधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
(छ) नोडल अधिकारी से प्रत्येक सरकारी संस्था द्वारा विकासकर्ता और सुलह समिति के साथ संवाद करने के लिए घोषित किया गया अधिकारी, अभिप्रेत है।	(छ) प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष (HOD) / सचिव, द्वारा नियुक्त वह अधिकारी होगा जो कि उस प्रकरण को सुलह समिति के समक्ष उसकी सहमति के लिये प्रस्तुत करेगा।

(ii)खण्ड (ज) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण– विभाग के प्रकरणों को सुलह समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय वह अधिकारी या उससे उच्च स्तर का अधिकारी लेगा जो उस विकास कार्य की स्वीकृति देने के लिये सक्षम है।"

(2) अनुलग्नक 2 में प्रस्तर–9.2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तर अतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"9.3 छोटे प्रकरणों (जिनमें विवाद रू0 50 लाख से कम हो) को सुलह समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये यह निर्णय लिया गया कि उनकी फीस के लिये विकासकर्ता से कोई भुगतान अग्रिम के रूप में नहीं लिया जायेगा। विवाद में समझौता होने पर अन्तिम भुगतान में यह शुल्क (Fees) (जो कि समिति द्वारा तय की जायेगी) विकासकर्ता से लिया जायेगा। समझौता न होने की स्थिति में पूर्ण फीस (सुलह समिति का व्यय) सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।"

उक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें / प्रावधान यथावत रहेगें।

(उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–146/VII-A-2/2022/11(सिडकुल)/2021 दिनांक 13.04.2022 का संलग्नक)

औद्योगिक विकास अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) का गठन

विषय : उत्तराखंड के सरकारी संस्थाओं की परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों/उद्योगपतियों/ठेकेदारों/रियायतियों/पट्टा–धारकों/आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों आदि के साथ विवादों के सुलह एवं समाधान हेतु व्यवस्था।

1. परिभाषाएं :

(क) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड की सरकार/शासन अभिप्रेत है;

(ख) 'सरकारी संस्था' से उत्तराखंड सरकार के सभी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/परिषद/निगम/अन्य संस्थायें, अभिप्रेत है;

(ग) 'विकासकर्ता' से सभी निवेशक/उद्योगपति/व्यवसायी/ठेकेदार/रियायती/पट्टाधारक/ सलाहकार आदि, जो सरकारी संस्थाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं/सेवाओं को संपादित/ निष्पादित करने में संलग्न हैं, अभिप्रेत है;

(घ) 'सी.सी.आई.सी.',से उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की जाने वाली स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति अभिप्रेत है;

(ङ) 'परियोजनायें' से सरकारी संस्था द्वारा निष्पादित सभी निर्माण अनुबंध/ईपीसी अनुबंध/ सार्वजनिक निजी भागीदारी/सेवा/आपूर्ति अनुबंध अभिप्रेत है;

(च) 'नोडल विभाग' से निदेशक, उद्योग (निदेशालय), उत्तराखंड शासन, अभिप्रेत है;

(छ) <u>प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष (HOD)/सचिव, द्वारा नियुक्त वह अधिकारी होगा जो कि उस प्रकरण को सुलह समिति के समक्ष उसकी सहमति के लिये प्रस्तुत करेगा।</u>

(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' से मुख्यमंत्री/मंत्री/सचिव/विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, अभिप्रेत है;

<u>स्पष्टीकरण : विभाग के प्रकरणों को सुलह समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय वह अधिकारी या उससे उच्च स्तर का अधिकारी लेगा जो उस विकास कार्य की स्वीकृति देने के लिये सक्षम है।</u>

(झ) 'सुलह के लिए सहमति' से अधिनियम और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सुलह के लिए सरकारी संस्था और विकासकर्ताद्वारा अनुमोदित स्वतः सहमति, अभिप्रेत है;

(ट) 'समाधान' से सीसीआईई के समक्ष विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा आपसी सहमति से नियत नियम और शर्तें अभिप्रेत है;

(ठ) 'अधिनियम' से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है।

2. उद्देश्य :

राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक सुविकसित बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण कारक है। विगत वर्षों में सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया है। इन सरकारी संस्थाओं के द्वारा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकासकर्ताओं के साथ समझौते किए गए हैं, जिनमें सरकारी संस्थाओं और विकासकर्ताओं के बीच विवाद भी उत्पन्न हुए

हैं। लंबित विवादों और दावों की समस्या ने गंभीर रूप धारण करते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के साथ–साथ परियोजनाओं की व्यवहार्यता को भी प्रभावित किया है।

अतः, उत्तराखंड शासन द्वारा व्यापार में आसानी और रोजगार सृजन के लिए "निवेशक अनुकूल वातावरण" विकसित करने के निमित्त सरकारी संस्थाओं और विकासकर्ताओं के मध्य विवादों के सुलह और समाधान हेतु 'स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया है।

उदाहरण :

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक निगम लि0 (सिडकुल) द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न प्रकार से कियान्वयन हेतु (आइटम की दर, संयुक्त उद्यम, ईपीसी, आदि)राज्य की ओर से विकासकर्ता के साथ विभिन्न अनुबंध/समझौते किए गए हैं। इन अनुबंधों/समझौतों के अंतर्गत कई विवाद उत्पन्न हुए हैं जिनमें न केवल अत्यधिक कानूनी व्यय शामिल हैं, बल्कि इन विवादों में शामिल दोनों पक्षों के बहुमूल्य मानव और प्राकृतिक संसाधनों का भी व्यपवर्तन हो रहा है। वर्तमान में, विभिन्न माध्यस्थम् अधिकरणों को 11 प्रकरण सन्दर्भित किए गए हैं, जिनमें कुल दावा राशि रू. 485 करोड़ निहित हैं। विवादों का शीघ्र और अदालत के बाहर समाधान सभी हितधारकों और राज्य की प्रगति के हित में है।

3. पृष्ठभूमि :

3.1 नीति आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14070/1412016–पीपीपीएयू दिनांक 05.09.2016 के द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा "निर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार के उपायों पर पहल" शीर्षक के साथ लिये गये निर्णय को सभी सम्बन्धितों/विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भेज कर उसमें निहित पहलों पर शीघ्र विचार करने और उनके कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। इन पहलों में, लंबित या नए मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 'स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति' की नियुक्ति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विवादों के समाधान की एक प्रणाली को स्थापित करना भी सम्मिलित है।

3.2 नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0 एन0 14070/04/2021–पी.पी.पी.ए.यू. दिनांकित 20 जुलाई, 2021 (ड्राफ्ट रिपोर्ट) द्वारा समाधान तंत्र की स्थापना तथा मानक प्रचालन प्रकिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.3 उत्तराखंड शासन द्वारा नीति आयोग के द्वारा निर्गत विवादों के समाधान हेतु तंत्र स्थापना एवं प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देशों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित उत्तराखंड राज्य की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सीसीआईई को सन्दर्भित किया जा सकता है।

4. स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति :

4.1 सीसीआईई में सामान्यतया 3 सदस्य होंगे।

4.2 समिति के सदस्यों का नामांकन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जायेगा एवं सुलह हेतु इच्छुक सम्बन्धित विकासकर्ता/अन्य पक्षकार की उपरोक्त सुलह समिति पर सहमति प्राप्त की जायेगी। जिन विकासकर्ता /अन्य पक्षकार के द्वारा सुलह समिति पर सहमति दी गयी है तो यह सहमति माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996(समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 63 एवं 64 के अन्तर्गत सहमति समझी जायेगी।

4.3 सदस्यों का कार्यकाल एवं नियुक्ति की शर्तें वह होंगी जैसा कि उनके नियुक्ति ओदश में उल्लिखित हो।

4.4 सी.सी.आई.ई से सम्बन्धित व्यापाक 'नियम एवं शर्तें' तथा कार्यक्षेत्र (T&R) **अनुलग्नक–1** में होगी। तदनुसार विकसित की गयी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को सुलह की कार्यवाही में लागू माना जायेगा।

4.5 उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन सीसीआईई के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा जोकि सुलह समिति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, सचिवालयी सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। ऐसी व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा छमाही आधार पर की जाएगी।

5. सीसीआईई की कार्यप्रणाली :

5.1 सुलह प्रक्रिया, 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित)' के भाग–III के अधीन संचालित की जाएगी।

5.2 सीसीआईई, उत्तराखंड सरकार द्वारा **अनुलग्नक–2** में यथानिर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार संचालित होगी।

5.3 समिति की किसी भी कार्यवाही के दौरान सदस्यों में से किसी एक के उपलब्ध न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, अन्य दो सदस्यों वाली समिति मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए सक्षम होगी और समिति की कार्यवाही दूषित नहीं मानी जायेगी यदि तीन सदस्यों में से एक समिति के विमर्श में उपस्थित नही हैं। तथापि, दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, सभी 3 सुलहकर्ता इसे प्रमाणित करेंगे और ऐसा समझौता दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

5.4 स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) या तो पक्षों के बीच विवाद (विवादों) को सुलझाने और निपटाने में सफ़ल होगी या फिर यह प्रक्रिया विफल हो सकती है। सीसीआईई के स्तर पर सुलह प्रक्रिया की विफलता की स्थिति में, पक्षकार सुलह प्रक्रिया से हट सकते है और मध्यस्थता/न्यायालयों की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकता है। सुलह की कार्यवाही सफल होने की स्थिति में, विवाद के पक्ष लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और सुलहकर्ता इसे प्रमाणित करेंगे। ऐसा समझौता 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996(समय–समय पर यथासंशोधित)' की धारा 73 के संदर्भ में पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

6. माध्यस्थम् अधिकरणों, न्यायालयों के समक्ष पहले से लंबित मामलों में प्रक्रिया :

6.1 माध्यस्थम् अधिकरणों या न्यायालयों के समक्ष लंबित विवादों के मामलों में, सरकारी संस्था द्वारा विकासकर्ता को अथवा विपरीततः, **अनुलग्नक–3** में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार आगे आने और सुलह समिति के माध्यम से सुलह की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रस्ताव दिया जायेगा। सरकारी संस्था तथा विकासकर्ता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुलह समिति को **अनुलग्नक–4** के अनुसार संयुक्त सन्दर्भ प्रस्तुत करेंगे जिस पर समिति ऐसे संदर्भ (संदर्भों) की जांच प्रारम्भ करेगी। जब भी पक्षकार सुलह समिति से समाधान हेतु सहमत होते हैं, वे सम्बंधित माध्यस्थम् अधिकरणों/न्यायलयों के समक्ष लंबित कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

6.2 समाधान हो जाने की स्थिति में पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय/मध्यस्थता प्रक्रिया से 30 दिनों के भीतर मामला वापस लिया जायेगा।

7. स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) की सिफारिशों पर नोडल विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई :

7.1 सरकारी संस्था और विकासकर्ता सीसीआईई के सिफारिशों/निर्णयों का सम्मान और क्रियान्वयन करेंगे।

7.2 सीसीआईई की सिफारिश/निर्णय प्राप्त होने पर नोडल विभाग द्वारा 7 कार्य दिवसों के भीतर, सरकारी संस्था और विकासकर्ता को विवाद, दावा राशि, निपटान राशि आदि के संक्षिप्त विवरण सहित सूचित किया जायेगा।

7.3 सरकारी संस्था और विकासकर्ता द्वारा सीसीआईई के निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जायेगी।

7.4 सरकारी संस्था और विकासकर्ता द्वारा निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने और माध्यस्थम् अधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले को यथासंभव 30 दिन के भीतर वापस लेने, यथा लागू, आदि दायित्वों को पूर्ण करने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। निपटान के अनुसार एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय भुगतान/वचनबद्धता की पूर्ति, निपटान तिथि से 30 दिनों (अथवा परस्पर सहमति की अवधि) के भीतर सम्बन्धित पक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उत्तराखंड सरकार द्वारा यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया है और यदि विकासकर्ता इस प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए सहमत नहीं हैं या कोई संकोच है, तो कोई बाध्यता नहीं है और उन्हें अन्य संगत कानूनी अनुतोष प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।

अनुलग्नक : 1

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के सामान्य नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions) तथा कार्यक्षेत्र (Terms of Reference):

1. तीन सदस्यीय सीसीआईई का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2. सदस्यों का कार्यकाल एवं नियुक्ति की शर्तें वह होंगी जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हो।
3. सुलह प्रक्रिया,' माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित)' के भाग III के तहत निष्पादित की जायेंगी।
4. सीसीआईई के एक सदस्य को कार्यवाही के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 25000/– मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।
5. सुलह समिति द्वारा अपनी पहली बैठक में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को निर्धारित किया जा सकेगा।
6. सीसीआईई द्वारा देहरादून में एक उपयुक्त स्थान पर अपनी दैनिक बैठकें आयोजित की जायेंगी और कार्य की अधिकता/व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए हर महीने जितनी उचित समझे, उतनी बैठकें आयोजित की जायेंगी। यह अपेक्षित है कि सुलह–सह–निपटान की कार्यवाही प्रत्येक मामले में 5 बैठकों के माध्यम से, किन्तु सीसीआईई को संदर्भ प्राप्त होने के दिन (संयुक्त सहमति पत्र प्राप्त करने की तिथि) से जो तीन महीने से अधिक नहीं होगी, की अवधि में पूरी की जायेगी। असाधारण मामले में, यदि किसी विशेष विवाद के लिए 5 से अधिक बैठकों की आवश्यकता होती है, तो समिति के विवेक पर केवल 7 बैठकों के लिए मानदेय के भुगतान के प्रतिबंधाधीन यथासम्भव न्यूनतम अतिरिक्त समय के साथ ऐसी बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।
7. सीसीआईई द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग से सौहार्दपूर्ण समाधान पर अपनी सिफारिशें दी जा सकती है।
8. सीसीआईई द्वारा संदर्भित मामलों के निस्तारण के लिए अपनी कार्यपद्धति/प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। पक्षकारों को स्पष्टता हेतु यह उल्लेखनीय है कि सीसीआईई की प्रक्रिया वैकल्पिक मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में नहीं है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावों/बचाव, तर्कों, प्रत्युत्तरों, लिखित निवेदनों आदि के साथ आते हैं। **सीसीआईई का मंच एक समझौता मंच है, जहां पक्षकारों के मध्य कानूनी द्वन्द के बजाय आपसी समझदारी आधारित आदान–प्रदान की भावना महत्वपूर्ण होती है,** इसलिए पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे अपने–अपने रुख के संबंध में सीसीआईई के समक्ष संक्षिप्त में तथा सुलह/निपटान की भावना से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
9. सुलह कार्यवाहियों के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, सुलह समिति द्वारा राज्य सरकार या उसकी संस्थाओं को अपने अनुबंध प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए समय–समय पर सलाह/सुझाव दिया जा सकता है।

अनुलग्नक : 2

सुलह के लिए स्थायी संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) :

सीसीआईई द्वारा परियोजनाओं में विवादों के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. सुलह की प्रक्रिया 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित)' की धारा 61 से 81 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।

2. **अधिनियम की धारा 62 के अनुसार सुलह की कार्यवाही का प्रारंभ :**

(क) सीसीआईई के माध्यम से सुलह के लिए सहमति देते हुए, विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक पत्र (अनुलग्नक–4)।

(ख) विकासकर्ता और सरकारी संस्था द्वारा सुलह के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों/विवादों का संक्षिप्त विवरण।

3. **विकासकर्ता एवं सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व :**

(क) **सरकारी संस्था :** सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधितः अधिकृत प्रतिनिधि ।

(ख) **विकासकर्ता :** सुलह समझौते में जाने के लिए विधितः विकासकर्ता द्वारा पारित प्रस्ताव और पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत वरिष्ठ कार्यकारी या नियमित कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जायेगा। ऐसे प्रतिनिधि को विकासकर्ता के संकल्प और मुख्तारनामा की प्रति सुलह समिति की पहली बैठक में या उससे पूर्व प्रस्तुत करना होगा **(अनुलग्नक–5 और 6)**।

पक्षों को सुलह प्रक्रिया के दौरान कानूनी पेशेवर को नियुक्त करने की अनुमति नहीं होगी।

4. सीसीआईई की पहली बैठक से पहले पक्षकार माध्यस्थम् अधिकरण/न्यायालय, यदि कोई हो, को उनके द्वारा सुलह प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सूचित कर सकते हैं।

5. **पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (प्रतीकात्मक, सीमित नहीं) :–**

(क) अनुबंध/रियायत समझौते की प्रति।

(ख) दावे (दावों) का विवरण और प्रतिरक्षा(ओं) का विवरण।

(ग) माध्यथम् पंचाट (आर्बिट्रल अवार्ड), माननीय न्यायालय के समक्ष दायर विवरण, न्यायालय द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति।

6. सीसीआईई द्वारा शीघ्रातिशीघ्र एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जायेगा। सीसीआईई द्वारा त्वरित निस्तारण हेतु जल्दी–जल्दी बैठकें की जायेंगी।

7. सीसीआईई, अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, जहाँ आवश्यक हो, दोनों पक्षों को समाधान की संभावित शर्तों के बारे में संस्तुति करेगी।

8. सहायता (अधिनियम की धारा–68 के तहत): सुलह समिति को ऐसी विशेषज्ञ तकनीकी और सचिवालयी सहायता प्रदान की जायेगी जैसा समिति द्वारा दक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु अपेक्षित हो। नोडल विभाग द्वारा समिति की संतुष्टि के अनुरूप इसकी व्यवस्था की जायेगी।

9.1 नोडल विभाग, प्रथम दृष्टया, सुलह की कार्यवाही पर होने वाला सभी व्यय वहन करेगा जिसमें सुलहकर्ताओं को मानदेय का भुगतान, कार्यालय स्थान का प्रावधान, समर्पित विशेषज्ञ एवं सचिवालयी सहायता, और अन्य अनुषंगिक व्यय शामिल हैं। अन्य पक्ष (विकासकर्ता) द्वारा सुलह की कार्यवाही शुरू करने के लिए नोडल विभाग में, यथासंभव अग्रिम रूप से, ₹ 3.00 लाख की राशि जमा की जायेगी।

9.2 नोडल विभाग द्वारा सुलह समिति की ओर से सुलह कार्यवाहियों पर हुए व्यय का लेखा–जोखा रखा जायेगा। सुलह की कार्यवाही समाप्त होने पर, नोडल विभाग सुलह की लागत का लेखा–जोखा सुलह समिति को प्रस्तुत करेगा, जिसे अंततः सुलह समिति के निर्देशों के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजित किया जाएगा।

9.3 <u>छोटे प्रकरणों (जिनमें विवाद रू0 50 लाख से कम हो) को सुलह समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये यह निर्णय लिया गया कि उनकी फीस के लिये विकासकर्ता से कोई भुगतान अग्रिम के रूप में नहीं लिया जायेगा। विवाद में समझौता होने पर अन्तिम भुगतान में यह शुल्क (Fees) (जो कि समिति द्वारा तय की जायेगी) विकासकर्ता से लिया जायेगा। समझौता न होने की स्थिति में पूर्ण फीस (सुलह समिति का व्यय) सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।</u>

10. <u>अवशिष्ट मामले</u> : सीसीआईई इस प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव के आधार पर समय–समय पर इस एसओपी की समीक्षा सहित किसी भी अवशिष्ट मामलें के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है। कोई भी परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

अनुलग्नक : 3

विभाग की परियोजनाओं में उत्पन्न विवादों के विवरण के साथ विकासकर्ताओं को भेजा जाने वाला पत्र।

संख्या :

तिथि :

विषयः .....विभाग, उत्तराखंड सरकार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सुलह समिति (सीसीआईई) की स्थापना।

प्रिय महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी संस्था और विकासकर्ता के बीच किसी भी संविदात्मक विवाद के समाधान के लिए प्रकरण सीसीआईई को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया है।

1. सुलह प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के समाधान और मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए सीसीआईई के गठन एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से सम्बन्धित प्रारूप संलग्न है। यह ज्ञातव्य है कि सीसीआईई का विस्तार माध्यथम् प्रक्रिया से पूर्व, उसके दौरान या पश्चात् के विवादों में व्याप्त है।
2. सरकारी संस्था सभी संबंधित मामलों में जिसमें मा0 न्यायालयों के समक्ष इसके द्वारा माध्यस्थम् पंचाट को चुनौती दी गयी है, को सीसीआईई द्वारा समाधान हेतु लिए जाने वाले समय तक, अपनी सहमति से स्थगित करने के लिए मा0 न्यायालय से उचित अनुरोध करने को तैयार है, यदि आप इससे सहमत हैं।
3. यदि आप वर्तमान में माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत लंबित विवादों को उक्त समिति को संदर्भित करने के लिए सहमत हैं, तो आप इस सुलह तंत्र का सहारा ले सकते हैं और माध्यस्थम् अधिकरण से यह अनुरोध कर सकते हैं कि जब तक कि सीसीआईई उक्त विवाद (विवादों) पर विचार करती है, तब तक निपटान की कार्यवाही को स्थगित रखने पर विचार किया जाए।
4. कृपया ध्यान दें कि सीसीआईई को विवाद (विवादों) को संदर्भित करने के लिए अपनी सहमति/इच्छा देकर, आप सुलह प्रक्रिया हेतु, विशेष रूप से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 63 और 64 में निहित प्रावधानों के लिए, अपनी स्वीकृति की भी पुष्टि कर रहे हैं और यह अधिनियम के तहत "सुलह" की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
5. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में विभाग के निम्नलिखित पते पर अपनी सहमति/इच्छा सूचित करने का कष्ट करें।

पता :
ई–मेल :
संपर्क नंबर :

भवदीय,

(विभाग के नोडल अधिकारी)

अनुलग्नक : 4

सीसीआईई को सहमति पत्र (सुलह के लिए सहमति हेतु दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित)

माननीय स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के समक्ष।

विषयः ..... (परियोजना का नाम) से संबंधित विवादों/दावों के निपटारे का प्रस्ताव

राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसार इंगित विषय .....(परियोजना का नाम) से सम्बन्धित विभिन्न विवादों/मुद्दों के समाधान के लिए प्राप्त सहमति के आधार पर दोनों पक्ष माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित) के भाग–III (समाधान) अनुसार सुलह के लिए सहमत हुए हैं। सुलह के लिए पक्षकारों की यह सहमति सीसीआईई द्वारा अंगीकृत कार्यप्रणाली/मानक संचालन प्रक्रियाओं के प्रति भी सहमति है, जैसा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट किया गया है।

सरकारी संस्था

विकासकर्ता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

संपर्क विवरण :

अनुलग्नक : 5

बोर्ड संकल्प के लिए प्रारूप

..... (विकासकर्ता का नाम) के निदेशक मंडल/न्यासी/सोसाईटी/अधिकृत पार्टनर/व्यक्ति (जिसे आगे 'अधिकारी' कहा गया है) द्वारा.....(स्थान) में दिनांक ..... को आयोजित बैठक में पारित संकल्प की सत्यापित प्रति।

"संकल्प किया गया कि श्री .....(नाम एवं पदनाम) (इसके बाद 'अधिकृत हस्ताक्षरी' के रूप में संदर्भित), जो कि .....के निवासी हैं, एतदद्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के समक्ष उपस्थित होने, प्रतिनिधित्व करने और सुलह समझौता निष्पादित करने के लिए विकासकर्ता.....की ओर से विकासकर्ता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने और पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करेंगे।"

परियोजना का नाम:

इस अभिलेख द्वारा सभी सूचित होवें कि हमारा .....(विकासकर्ता का नाम), जिनका पता ..... है, का प्रतिनिधित्व ..... (नाम व पदनाम जिसे आगे 'वरिष्ठ अधिकारी' कहा गया है) श्री .... द्वारा किया जायेगा।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि विकासकर्ता की सहमति से श्री ..... को विकासकर्ता की ओर से ..... (अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम/पदनाम) के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित/प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आगे संकल्प किया गया कि उक्त मुख्तारनामा पर विकासकर्ता के ..... द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

नमूना हस्ताक्षर 1.

2.

3.

द्वारा प्रमाणित

.....

हस्ताक्षर (वरिष्ठ अधिकारी)

अनुलग्नक : 6

मुख्तारनामा के लिए प्रारूप :

मुख्तारनामा

इस अभिलेख द्वारा सभी सूचित होंवे कि हम....., (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय/पत्राचार पता (बाद में 'पता' के रूप में सन्दर्भित)..... ..... में है, के प्रतिनिधि श्री ..... पुत्र श्री....., जो वर्तमान में ..... में निवास कर रहे हैं, को हमारे द्वारा नियोजित किया गया है और अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में हमारे सच्चे और वैध कानूनी प्रतिनिधि हैं (आगे "एटॉर्नी" के रूप में संदर्भित) और इस रूप में ..... (परियोजना का नाम) जिसे..... (सरकारी संस्था का नाम), द्वारा प्रस्तावित/विकसित किया जा रहा है, के सम्बन्ध में सी.सी.आईई के समक्ष गतिमान सभी मामलों में हमारी ओर से उपस्थित होने, पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत/अभिलिखित करने, हमारा प्रतिनिधित्व करने, सुलह समझौते सहित सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित/निष्पादित करने तथा सुलह की कार्यवाही से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में सरकारी संस्था से संव्यवहार करने हेतु अधिकृत होंगे।

और, हम एतदद्वारा अनुसमर्थन और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं तथा इस मुख्तारनामा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए या किए जाने वाले सभी कार्यों, समझौता और कार्यवाही का अनुसमर्थन और पुष्टि करते हैं; और यह हमें स्वीकार है कि हमारे उक्त अटार्नी द्वारा एतदद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए सभी कार्य, समझौता और कार्यवाही हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

हम, ... (विकासकर्ता का नाम), ने दिनांक.....को निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में इस मुख्तारनामा को निष्पादित किया है।

द्वारा..... (विकासकर्ता का नाम)

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ अधिकारी

गवाहः
1.
2.

स्वीकृत

(हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और पता

मेरे समक्षः
नोटरी का नाम और पता

आज्ञा से,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Office Memorandum No.146/VII-A-2/2022/11-SIIDCUL-2021, dated April 13, 2022.

Office Memorandum

April 13, 2022

No. 146/VII-A-2/2022/11-SIIDCUL-2021--The Governor, is pleased to allow to make the following amendments in OM No-1269/VII-A-2/2021/11-SIIDCUL/2021 dated 25.10.2021.

In para 1:-

(i) For the existing provision of clause (g) as set out in Column-1 below the provision as set out in column-2, shall be substituted namely -

Column-1	Column-2
Existing Provisions to be	Hereby Substituted Provisions
(g) Nodal Officer means to be declared by each Government Entity to communicate with the Developer and CCIE.	(g) The Nodal Officer in each department shall be the officer appointed by the Head of Office (HOO)/Secretary, who shall present that case before the Conciliation Committee, for its consent.

(ii) in clause (h) the following explanation shall be inserted, namely:-
"Explanation: The decision to present the matters of the department before the conciliation committee shall be taken by the officer or above level officer who is competent to give approval for that development work."

(2) In annexure 2, after para 9.2, the following para shall be inserted, namely:
" 9.3 In order to present the small cases (in which dispute is less than Rs. 50 lakhs) before the Conciliation Committee, it is decided that no payment shall be taken from the developer for their fees as advance. After settlement of dispute, this fee (which shall be decided by the committee) shall be taken from the developer in the final payment. In case of no settlement, the full fee (expenses of the Conciliation Committee) shall be borne by the Government."

Other conditions/provisions of the said office memorandum shall remain the same.

Annexure of the Office Memorandum No.146/VII-A-2/2022/11-SIIDCUL-2021 Dated 13/04/2022 of the Uttarakhand Government

Industrial Development Section-2
Government of Uttarakhand

Constitution of Conciliation Committee of independent Experts (CCIE)

Subject: Conciliation and Settlement Mechanism for Contractual Disputes with the Investors/Industrialists/Contractors/Concessionaires/Lease Holders/Suppliers/ Consultants etc in respect of Projects of various Government Entities of Uttarakhand.

1. Definitions

(a) **"State Government"** means Government of Uttarakhand;

(b) **"Government Entity"** means all Departments/ PSUs/ Boards/ Corporations/ other entities of Government of Uttarakhand;

(c) **"Developers"** means all Investors/ Industrialists/ Businessmen/ Contractors/ Concessionaires/ Lease holders/ Consultants etc engaged by Government Entities to deliver/execute projects and Services;

(d) **"Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE)"** means Committee of independent experts to be constituted by Competent Authority of Government of Uttarakhand;

(e) **"Projects"** means all Construction Contracts/ EPC Contracts/ Public Private Partnerships/ Service/Supply Contracts executed by developers as mandated by Government Entities;

(f) **"Nodal Department"** means Director Industries, Department of Industries, Government of Uttarakhand;

(g) **"Nodal officer"** in each department shall be the officer appointed by the Head of Office (HOO)/Secretary, who shall present that case before the Conciliation Committee, for its consent.

(h) **"Competent authority"** means Chief Minister/ Minister/ Secretary/ Head of Department/Managing Director of PSUs or any officer authorised by the State Government;

Explanation- The decision to present the matters of the department before the conciliation committee shall be taken by the officer or above level officer who is competent to give approval for that development work.

(i) **"Consent for Conciliation"** means with deemed approval from Government Entity and Developer for conciliation as per policies and procedures, as prescribed in Act and SOP;

(j) **"Settlement"** means Terms and Conditions mutually agreed by Developer and Government Entity in the presence of CCIE;

(k) **"Act"** means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

2. Objective:

A well-developed state infrastructure is a crucial factor for the economic growth of the state. Over the years, efforts have been made to accelerate the pace of development in the entire state through its various Government Entities. These Government Entities have further entered into agreements with Developers to implement projects which have also given rise to disputes between Government Entities and Developers. The problem of pending disputes and claims has assumed serious proportions and has hampered the viability of the aforesaid projects along with delay in the delivery/execution of the projects as well.

Therefore, Government of Uttarakhand, keeping in mind, the *ease of doing business* and to develop *investor friendly environment* to inter alia, generate employment, generation, has decided to constitute a panel of independent experts for conciliation and settlement of the disputes between the Government Entities and Developers.

Case Example

The State Infrastructure and Industrial Corporation of Uttarakhand Ltd. (SIIDCUL) has entered into various contract agreements with the Developers on behalf of The State for implementing the projects in various modes [Item Rate, Joint Ventures, EPC, etc.]. Several disputes have arisen under these contract agreements which are not only involving exorbitant legal costs, but also causing diversion of precious human and natural resource of both parties involved in these disputes. At present, 11 references have been made to various Arbitral Tribunals further entailing a total claim amount of INR 485 crores. The early and out-of-court settlement/Resolution of disputes is in the interest of all the stakeholders and State's progress.

3. Background:

3.1 NITI Aayog while communicating decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) vide its OM No. 14070/1412016-PPPAU dated 5th September 2016, titled "Initiatives on the measures for revival of the Construction Sector - Reg.", directed all the concerned Departments/ Ministries/ Public sector Units to expeditiously examine the initiatives contained therein and take action for their implementation. The initiatives, inter alia, include establishing a system of conciliation of disputes for amicable settlement through appointment of Conciliation Committees comprising of independent experts in order to ensure speedy disposal of pending or new cases.

3.2. Directions pertaining to development of conciliation mechanism and Standard Operating Procedures (SOPs) have been issued through Office Memorandum No. - N-14070/04/2021-PPPAU, Dated 20th July, 2021 of Niti Aayog.

3.3 The Govt. of Uttarakhand, considering NitiAayog's advisory on establishing the procedure of conciliation of disputes, has decided that the dispute matters pertaining to various projects of the State of Uttarakhand being executed through Government Entities may be referred to the CCIE to settle disputes.

4. Conciliation Committee of Independent experts

4.1 CCIE shall normally be having 3 Members.

4.2 Nomination of the members of the committee shall be done by the Uttarakhand Government and the consent of the concerned developer/other party willing for reconciliation shall be obtained on the above conciliation committee. If the developer/ other party has agreed to the Conciliation Committee, then this consent shall be deemed to have been agreed under Section 63 and 64 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

4.3 Term and Tenure of the appointment of Members shall be same as mentioned in their respective appointment orders.

4.4 The broad Terms & Conditions and the Terms of Reference of the CCIE are Enclosed at Annexure - 1. The procedures and methodologies so developed shall be deemed to be applicable in conciliation proceedings.

4.5 Directorate Industries, Government of Uttarakhand would act as Secretariat for CCIE, and shall arrange for the required infrastructure, Secretarial Assistance and other facilities to the Conciliation Committee. The expenses on such arrangements shall be reimbursed by State Government on half yearly basis.

5. Functioning of the CCIE

5.1 The Conciliation process shall be conducted under Part III of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

5.2 CCIE shall operate with standard operating procedures (SOPs) as prescribed by Government of Uttarakhand as enclosed at Annexure 2.

5.3 The possibility of non-availability of any one of the members of a Committee in any proceedings cannot be ruled out. As such, the Committee comprising of the other **two members** shall be competent to proceed in the matter and the proceedings of the Committee shall not be vitiated if one of the three members is not present in the deliberations of the Committee. Whereas, while signing the settlement agreement (between parties), all 3 conciliators shall authenticate the same and the settlement agreement shall be binding on the parties.

5.4 The CCIE would either be able to resolve and settle the dispute(s) between the parties, or the process may fail. In case of failure of the conciliation process at the level of the CCIE, the parties may withdraw from conciliation process and take recourse to the laid down legal process of arbitration/ Courts. In the event of the conciliation proceedings being successful, the parties, to the dispute, would sign the written settlement agreement and the conciliators would authenticate the same. Such settlement agreement would then be binding on the parties in terms of Section 73 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

6. Procedure in cases already pending before the Arbitral Tribunals, Courts:

6.1 In cases of disputes pending before the Arbitration Tribunals or the Courts, the Government Entity shall make an offer to the Developer or vice versa to come forward and explore the possibilities of conciliation through the Conciliation Committee as per template communication enclosed at Annexure - 3. The Government Entity and Developer will make an appropriate joint reference to the Conciliation Committee with approval of competent authority, upon which the Committee shall proceed to examine such reference(s) in template communication enclosed at Annexure - 4. However, whenever the parties agree to reach out to the Conciliation Committee, they may request concerned courts/arbitral process to keep the proceedings in abeyance.

6.2 In case of settlement, parties shall withdraw the case from concerned courts/ Arbitral process within 30 days of Settlement.

7. Follow-up action by Nodal department on the recommendations of the CCIE:

7.1 The Government Entity and Developer would honour and implement the recommendations/ decisions of the CCIE.

7.2 Once the recommendation/decision of the CCIE is received, Nodal department shall inform the Government Entity and Developer along with the brief details of dispute by the party, claim amount, settlement amount etc., within 7 working days.

7.3. The Government Entity and Developer shall process the proposal for obtaining the concurrence/approval of the Competent Authority in order to actualise the decision taken by CCIE.

7.4 The Government Entity and the Developer shall take prompt action to fulfil their respective obligations for signing of the settlement agreement, as the case may be, including withdrawal of the case(s) pending before the Arbitration Tribunals/ Courts, preferably within a period of 30 days. The payments/commitment due from one party to the other party as per the settlement shall be made/fulfilled by either party within a period of 30 days (or mutually agreed days) from the settlement date.

8. It may be noted that this is an alternate dispute resolution mechanism being put in place by the Government of Uttarakhand and if the Developer is not willing to take recourse to this process or has any reluctance, whatsoever, then, there is no compulsion and they are free

Annexure-1

The Broad Terms and Conditions and the Terms of Reference of CCIE

1. The CCIE of 3 members shall be constituted by the State Government.

2. Term and Tenure of the appointment of Members shall be same as mentioned in their appointment letter.

3. The conciliation process will be conducted under Part III of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time)

4. A member of the CCIE shall be paid remuneration of INR 25000/- for each day of proceedings.

5. The Conciliation Panel in the first meeting may evolve its own procedures and methodologies for undertaking the functions.

6. The CCIE shall hold its day to day sittings at a suitable place in Dehradun and may hold as many sittings every month as it deems appropriate keeping in view the volume of work at its disposal. It is expected that the Conciliation-cum settlement proceedings shall be completed in each case through 5 sittings in a period of not more than **three months** from the day of reference (Date of receiving of Joint consent letter) is made to the CCIE. In exceptional case, if any particular dispute requires more than 5 sittings, the same may be held at the discretion of the committee with a cap on the payment of remuneration for 7 sittings only, and with the minimum possible time over run.

7. The CCIE may give its recommendations on amicable settlement separately for each contract.

8. The CCIE may develop its own procedures /process for dealing with matters referred to it. However, for the understanding of the parties, it may be noted that the procedure of CCIE may not be treated as alternative arbitration proceedings, whereby both parties come with Statement of Claims/Defence, arguments, rejoinders, written submissions, etc. aided by their respective lawyers. **The forum of CCIE is a settlement forum, where mutual give and take constitutes the essence, rather than strict legal position of the parties.** Hence, the parties are expected to be brief and to the point in front of CCIE with regard to their respective stand and view the exercise in the spirit of conciliation /Settlement.

9. Based on the experience gained in the course of Conciliation proceedings, the Conciliation Committee may suggest/recommend advisories to the State Government or its entities from time to time for improvement in its contract management Systems.

Annexure-2

Standing Operating Procedures (SOPs) for conciliation

The following procedure shall be adopted for conciliation of disputes in projects by CCIEs.

1. The procedure for conciliation shall be as prescribed in sections 61 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time).

2. **Commencement of Conciliation proceedings** in terms of section 62 of the Act

   (a) A letter jointly signed by Developer and Government Entity, consenting to conciliation through CCIE in suggestive template (Annexure - 4).
   (b) Brief statements from Developer and Government Entity, containing issues/ dispute(s) to be taken up for conciliation.

3. Representation from Developer and Government Entity
   (a) Government Entity: Representative duly authorised by the competent authority.
   (b) Developer: Must be represented by Senior executive or Regular employee of developer, supported by a Board resolution and Power of Attorney, duly authorised to enter into conciliation agreement. Representative must submit board resolution and power of attorney on or before first hearing in the template format (Annexure - 5 and 6)

The parties shall not be permitted to engage legal professional during conciliation process

4. Parties may inform the arbitral tribunal/court, if any, regarding initiation of conciliation process by them.

5. List of documents (suggestive, not limited) to be submitted by the parties.
   (a) Copy of contract/concession agreement
   (b) Copy of Statement of Claim(s) and Statement of Defence(s).
   (c) Copy of Arbitral award, Statements filed before the Hon'ble court, orders passed by court, if any.

6. CCIE may try to reach to an amicable solution as early as possible. For speedy disposal, CCIE may hold frequent meetings.

7. CCIE will give recommendation about possible terms of settlement to both parties, wherever necessary, as per section 73 of the Act.

8. **Assistance (in furtherance of Section - 68 of the Act):** The Conciliation Committee shall be assisted by such expert, technical and secretarial assistance, as it may be required for efficient discharge of its functions. The Nodal department may provide arrangements for the same to the satisfaction of the Committee.

9. Costs of Conciliation and Deposits:

9.1 Nodal Department, in the first instance, shall incur all expenditure on the conciliation proceedings including payment of remuneration to the conciliators, provision of office space, expenditure on dedicated expert and secretarial assistance and other incidental expenses. The other party (Developer) shall also deposit an amount of Rs.3 Lakhs, preferably as an advance, with Nodal department to commence the conciliation proceedings.

9.2 The Nodal Department shall maintain the accounts of expenditure incurred on the conciliation proceedings on behalf of the Conciliation Committee. Upon termination of conciliation proceedings, the Nodal department may render an account of the cost of conciliation, which shall finally be decided/ apportioned between/ among the parties as per the directions of the Conciliation Committee.

9.3 In order to present the small cases (in which dispute is less than Rs. 50 lakhs) before the Conciliation Committee, it is decided that no payment shall be taken from the developer for their fees as advance. After settlement of dispute, this fee (which shall be decided by the committee) shall be taken from the developer in the final payment. In case of no settlement, the full fee (expenses of the Conciliation Committee) shall be borne by the Government.

10. Residuary matters:

The CCIE may decide on the procedures to be followed in respect of any residuary matters, including the review of this SOP from time to time, based on the experience gained in the process. Any changes, if required, may be approved by the Competent Authority.

Annexure 3

Letter to be sent to the Developers with disputes in Department's Projects

No.
Date:

Subject: Establishment of Conciliation Committees of Independent Expert (CCIE) for conciliation of disputes pertaining to XXXX Department, Government of Uttarakhand.

Dear Sir/Madam,

I have been directed to inform you that the Government of Uttarakhand has decided to refer any contractual disputes between the Government Entity and the Developer to the CCIE for conciliation/ settlement of disputes.

1. The Standard Operating Procedures (SOP) for conciliation and settlement of disputes through the conciliatory process and the constitution of the CCIE is attached as Annexure. It may be noted that the scope of the CCIE pervades across disputes before, during or after the Arbitral process.

2. The Government Entity is agree to refer all the cases filed by it before the Hon'ble Courts challenging the Arbitral Awards with appropriate request to the Hon'ble Courts for holding the proceedings in these matters in abeyance for such time as may be taken by the CCIE for settlement of the related disputes in case you are agreeable to the same.

3. Further, in case you are agreeable to refer the disputes presently under Arbitral proceedings to the said Committee, you may also take recourse to this conciliatory and settlement route with appropriate request to the Arbitral Tribunals to consider the holding of the proceedings in abeyance till such time the said dispute(s) is/ are considered by the CCIE.

4. Please take note that by giving your consent/ willingness to refer the dispute(s) to the CCIE, you are also confirming your acceptance of the conciliation process, more specifically to the provisions contained in Sections 63 and 64 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996(as amended from time to time), and that it meets the requirements on "conciliation" under the Act ibid.

5. Accordingly, you are requested to indicate your consent/willingness in this regard at the following address of the _____ Department.

Address:_

E-mail:_

Contact No._

Yours Sincerely,

(Nodal officer of the department)

Annexure-4

Consent letter to CCIE (Signed by both parties, consenting to conciliation)

Before Hon'ble Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE)

Sub: Proposal for settlement of Disputes/Claims pertaining to the subject (Project Name)

Having consented for conciliation of different disputes/issues of the subject (Project Name) as per the Office Memorandum No. ———— Dated————, the parties have agreed for conciliation as per Part - III (Conciliation) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time). This consent of the parties for conciliation is also the consent to the methodology/ standard Operating Procedures to be adopted by the CCIE, as brought out in the above Office Memorandum, issued by the Government of Uttarakhand.

Developer **Government Entity**

Authorised Signatory (Sign)

Name

Address

Contact details

Annexure 5

Form for Resolution

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS/ TRUSTEES/SOCIETY OFFICIALS/DESIGNATED PARTNER/INDIVIDUAL (hereinafter called, 'Official") OF ————(Name of the Developer) AT THEIR MEETING HELD ON ————(Date) AT THE ——————(Address of the Developer) (hereinafter called, 'address').

"RESOLVED THAT Mr. ————————————(Name and Designation) (hereinafter referred to as "Authorised Signatory"), resident of ———— —— be and is hereby severally authorised to appear, represent and execute a conciliation agreement on behalf of the ————(Name of Developer), before the Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE), in the best interest of the Developer for the following work.

Name of the Project:

KNOW ALL MEN by these present that we, ————(Name of Developer), having our address at ————————, are represented by Sh ———— —(Name and Designation of Developer)(hereinafter called, 'Senior Official).

RESOLVED FURTHER THAT the consent of the developer is here by accorded and authorised to Sh———————— (Name of Senior official) of the Developer to execute and grant Power of Attorney in favour of ————————(Name and Designation of Authorised Signatory).

RESOLVED FURTHER THAT THE SAID Power of Attorney be signed by ——— ——— of the Developer.

Specimen Signature
1.

2.

3.

Attested by

———

Signature
(Senior official)

Annexure 6

Form for Power of Attorney

POWER OF ATTORNEY

Know all men by these Presents, We, ——— (Name of Developer) having its registered office (or Communication address) at ———— (Hereinafter referred as 'address') are represented by Mr ——, son of Shri ————and presently residing at " ————", who is presently employed with us and shall hold the position of Authorised Signatory and our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the "Attorney") to act severally and to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with our incidental to conciliation proceedings for the ————————(Project Name) proposed or being developed by the _____(Government Entity) (Hereinafter referred as "Government Entity") including but not limited to signing and submissions of all applications and other documents and writings, participate in meetings, representing us in all matters before CCIE, signing and execution of all documents including the Conciliation Agreement, undertakings consequent to conciliation proceedings, and generally dealing with Government Entity in all matters in connection with or relating to or arising out of conciliation proceedings for the said project.

AND we hereby agree to ratify and confirm and do hereby ratify and confirm all acts, deeds and things done or caused to be done by our said Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to be have done by us.

IN WITNESS WHEREOF WE, ——— (Developer), THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS ——— —DAY OF ————.

For ————————— (Developer)

Signature
(Name and Designation of Senior official of Developer)

Witnesses:

1.

2.

Accepted

(Signature)
Authorised Signatory and address

BEFORE ME
Name and address of Notary

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,
Secretary.

पी0एच0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/271—भाग 1—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मई, 2022 ई0 (बैशाख 17, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 102/UHC/Admin.A/2022--Shri Ramesh Singh, Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Nainital in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 103/UHC/Admin.A/2022--Shri Arun Vohra, Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), Haridwar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Champawat, vice Ms. Shivani Pasbola.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 104/UHC/Admin.A/2022--Ms. Gunjan Singh, Additional Judge, Family Court, Roorkee, District Haridwar is repatriated, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 105/UHC/Admin.A/2022--Shri Mohammad Yusuf, Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is posted as Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 106/UHC/Admin.A/2022--Shri Bhavdeep Ravtey, Chief Judicial Magistrate, Almora is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh, District Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 107/UHC/Admin.A/2022--Ms. Rinky Sahni, Civil Judge (Sr. Div.), Almora is posted as Chief Judicial Magistrate, Almora, vice Shri Bhavdeep Ravtey.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 108/UHC/Admin.A/2022--Ms. Shivani Pasbola, Chief Judicial Magistrate, Champawat is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Champawat, vice Ms. Nazish Kaleem.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 109/UHC/Admin.A/2022--Shri Rajeev Dhawan, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar, vice Shri Jayendra Singh.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 110/UHC/Admin.A/2022--Ms. Chhavi Bansal, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli, vice Shri Akhilesh Kumar Pandey.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 111/UHC/Admin.A/2022--Shri Sandip Kumar Tiwari, Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is repatriated, transferred and posted as Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Dehradun.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 112/UHC/Admin.A/2022--Ms. Sweta Pandey, Joint Secretary (Law)-cum-Joint L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun is repatriated, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag, vice Shri Sachin Kumar Pathak.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 113/UHC/Admin.A/2022--Ms. Shweta Rana Chauhan, Joint Registrar (Judicial & Admin.), Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun is repatriated, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Uttarkashi. in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 114/UHC/Admin.A/2022--Ms. Tricha Rawat, Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is repatriated, transferred and posted as Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar, vice Shri Rajeev Dhawan.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 115/UHC/Admin.A/2022--Shri Sanjeev Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 116/UHC/Admin.A/2022--Shri Sandeep Singh Bhandari, Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Almora, vice Ms. Rinky Sahni.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 117/UHC/Admin.A/2022--Ms. Neha Qayyum, 3rd Additional Civil Judge (Sr.Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal, vice Ms. Anita Kumari.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 118/UHC/Admin.A/2022--Ms. Nazish Kaleem, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, vice Shri Mohammad Yusuf.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 119/UHC/Admin.A/2022--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Chhavi Bansal.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 120/UHC/Admin.A/2022--Shri Akhilesh Kumar Pandey, Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), Haldwani, District Nainital, vice Ramesh Singh.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 121/UHC/Admin.A/2022--Shri Imran Mohammad Khan, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is repatriated, transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), Roorkee, District Haridwar, vice Ms. Simranjit Kaur.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 122/UHC/Admin.A/2022--Shri Sachin Kumar Pathak, Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, vice Shri Sanjeev Kumar.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 123/UHC/Admin.A/2022--Ms. Durga, Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi is repatriated, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 124/UHC/Admin.A/2022--Shri Puneet Kumar, Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Nainital, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 125/UHC/Admin.A/2022--Shri Alok Ram Tripathi, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is posted as Principal Magistrate 1st Class., Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, vice Shri Hemant Singh.

These transfer orders will come into force w.e.f. 15.04.2022.

Note:

(A) Recommendation for the name of Shri Jayendra Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for his posting as Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar, vice Ms. Tricha Rawat.

(B) Recommendation for the name of Shri Hemant Singh, Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is being sent the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for his posting as Secretary, District Legal Services Authority, Champawat, in the vacant post.

(C) Recommendation for the name of Shri Avinash Kumar Srivastava, Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for his posting as Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal, vice Shri Ashok Kumar.

NOTIFICATION

April 04, 2022

No. 137/UHC/Admin.A/2022--Shri Arvind Kumar, Registrar, State Consumer Dispute Redressal Commission, Uttarakhand, Dehradun is attached with High Court of Uttarakhand, Nainital as Office on Special Duty (OSD) with immediate effect. However he will not hand over the charge of his present assignment till further orders.

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

April 07, 2022

No. 138/XIV/a-42/Admin.A/2017--Shri Shambhu Nath Singh Sethwal, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 24.01.2022 to 29.01.2022 with permission to prefix 23.01.2022 as Sunday holiday and suffix 30.01.2022 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

I/c Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

After availing Child Care Leave

April 12, 2022

No. 1914/XIV-71/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 12.04.2022 after availing Child Care Leave of 15 days w.e.f. 28.03.2022 to 11.04.2022 with permission to prefix 27.03.2022 as Sunday.

NEENA AGGARWAL,

Registrar (Inspection)

U.H.C. Nainital.

Countersigned,

illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over)

For Child Care Leave

April 12, 2022

No. 1915/XIV-71/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital was handed over by the undersigned in the evening of 26.03.2022 for availing Child Care Leave of 15 days w.e.f. 28.03.2022 to 11.04.2022 with permission to prefix 27.03.2022 as Sunday, sanctioned vide letter No. 1407/XIV-71/Admin.A/2003 Dated 22.03.2022.

NEENA AGGARWAL,

Registrar (Inspection)

U.H.C. Nainital.

Countersigned,

illegible,

Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/271–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।